राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लि0

पश्चिम ब्लॉक, नेहरु सहकार भवन, 22 गोदाम सर्किल, जयपुर
फोन नं. 0141–2740930, 2740440 फैक्स:– 0141–2740930, 2740440
Email : rsldbpnd@yahoo.in Website : www.rsldb.nic.in

क्रमांक:फा.33/आ.वि./ईडीईजी/2018–19/21768-850 दिनांक : 29/11/18

सचिव,
प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि.,
————————।

विषय:– वर्ष 2018–19 के दौरान केन्द्रीय प्रयोजित योजना–"राष्ट्रीय पशुधन मिशन"– ईडीईजी घटक के कार्यान्वयन का प्रशासनिक अनुमोदन।

प्रसंग:– नाबार्ड का पत्र क्रमांक राबैं.पु.वि./जीएसएस/1510/एनएलएम–1/2018–19 दिनांक 14.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत नाबार्ड का पत्र क्रमांक राबैं.पु.वि./जीएसएस/1510/एनएलएम–1/2018–19 दिनांक 14.09.2018 (परिपत्र संख्या 241/पु.वि.–65/2018–19) की प्रति संलग्न कर लेख है कि वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन (ईडीईजी) अन्तर्गत वितरित किये जाने वाले ऋणों में पोल्ट्री वेंचर केपिटल फंड (पीवीसीएफ), एकीकृत छोटे रोमन्तक (जैसे भेड़/बकरी पालन) और खरगोशों का समन्वित विकास, सूअर विकास (पीडी), नर भैंसा बच्चों का रक्षण और पालन (एसएमबीसी) हेतु योजना 2018–19 के लिए जारी रखी गई है। वर्ष 2018–19 हेतु इस योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दु निम्न प्रकार है :–

1. राजस्थान राज्य के लिए योजनान्तर्गत 569 लाख रूपये का बजटीय प्रावधान (Gen./other 450 lakh, ST- 60 lakh, SC-59 lakh) रखा गया है, जिसका उपभोग वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक एवं अन्य संस्थायें, जो नाबार्ड से पुनर्वित्त हेतु पात्र है, द्वारा किया जावेगा।
2. सब्सिडी प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध रहेगी, अतः राज्य हेतु निर्धारित बजट का पूर्ण उपभोग होने के बाद अनुदान दावे Portal पर अपलोड नहीं हो सकेंगे।
3. सामान्य वर्ग के लिये केपिटल सब्सिडी प्रोजेक्ट कोस्ट की 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिये प्रोजेक्ट कोस्ट की 33.33 प्रतिशत रहेगी।
4. प्रोजेक्ट कोस्ट की न्यूनतम 10 प्रतिशत मार्जिन मनी होनी आवश्यक है।
5. परियोजना पूर्ण करने की समय–सीमा परियोजना में किए गए प्रावधान के अनुसार ऋण की पहली किश्त के वितरण तिथि के बाद अधिकतम 12 महिने के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी, लाभार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त पाए जाने पर बैंक इस अधिकतम अवधि को 3 महिने तक बढ़ा सकता है।
6. योजनान्तर्गत सब्सिडी प्राप्त करने हेतु सदस्य का आधार नम्बर एवं मोबाईल नम्बर होना आवश्यक है।
7. सब्सिडी प्राप्त होने पर प्राथमिक बैंक द्वारा इसे सब्सिडी रिजर्व फण्ड खातें में रखी जावेगी, जिसका ऋणीवार विवरण बैंक स्तर पर संधारित किया जावेगा।
8. सब्सिडी की राशि का समायोजन, 3 वर्ष की लॉक–इन अवधि के बाद ही ऋणी की अंतिम कुछ किश्तों पेटे किया जावेगा। इस लॉक–इन अवधि में खाता एन.पी.ए. होने पर सब्सिडी राशि वापिस नाबार्ड को भिजवाई जावेगी।

अतः योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि –

1. प्राथमिक बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के 3 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में Excell Sheet में Soft Copy राज्य बैंक के E-Mail rsldbpnd@gmial.com पर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे ताकि राज्य बैंक द्वारा नाबार्ड के Ensure Portal पर दावें अपलोड किये जाकर सब्सिडी की पात्र राशि को ब्लॉक किया जा सके।
2. प्राथमिक बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के 30 दिवस के भीतर प्रथम किश्त जारी की जावे।
3. प्राथमिक बैंक द्वारा प्रथम किश्त वितरण की सूचना ऋण वितरण के 7 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप में Excell Sheet में Soft Copy राज्य बैंक के E-Mail - rsldbpnd@gmial.com पर आवश्यक रूप से भिजवाई जावे ताकि राज्य बैंक द्वारा नाबार्ड के Ensure Portal पर ऋण वितरण सम्बन्धी सूचना अपलोड की जा सके।
4. प्रथम किश्त वितरण के 30 दिवस के भीतर यदि सूचना पोर्टल पर अपडेट नहीं की जाती है तो पोर्टल द्वारा आवेदन को डिलीट कर दिया जावेगा, अतः प्राथमिक बैंक उपरोक्त बिन्दु के अनुसार प्रथम किश्त वितरण की सूचना ऋण वितरण के 7 दिवस के भीतर उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें।
5. प्राथमिक बैंक द्वारा सब्सिडी की राशि प्राप्त होने के 7 दिवस के भीतर निम्नानुसार एक उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्य बैंक को प्रस्तुत किया जावेगा –

   "It is certified that subsidy amount of ..... loanee has been received from NABARD and same has been credited to subsidy reserve account (SRFA) of beneficiary. Details of beneficiaries is as under-"

   योजनानुसार, यह प्रमाण पत्र राज्य बैंक द्वारा Portal पर अपलोड किया जावेगा।

नाबार्ड से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न कर पठाई जा रही है। आपके द्वारा योजना का पूर्ण अध्ययन कर योजनानुसार आवश्यक कार्यवाही सम्पादित किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(राजीव लोचन)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अध्यक्ष/प्रशासक, प्राथमिक बैंक .....
2. उप महाप्रबन्धक लेखा एवं वित्त, को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि नाबार्ड से अनुदान की राशि प्राप्त होने की तिथि को ही इसे प्रा.बैंक को पासऑन किया जाना सुनिश्चित करावें।
3. सहायक महाप्रबन्धक, निरीक्षण एवं सुपरविजन/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, बैंक।
4. क्षेत्रीय प्रबन्धक, रा.रा.स.भू.वि.बैंक लि., क्षेत्रीय कार्यालय, ——————।
5. प्रबन्ध निदेशक, प्रकोष्ठ, बैंक।

प्रबन्ध निदेशक

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पुनर्वित विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बांद्रा (पू) मुंबई -400051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फैक्स :+911 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • website :www.nabard.org

NABARD

National Bank for Agriculture and Rural Development
Department of Refinance
Head Office: BKC, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Tel. +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • website : www.nabard.org

संदर्भ सं.राबैं.पु.वि. /जीएसएस/ 1510 /एनएलएम-1/2018-19

14 सितंबर 2018

परिपत्र सं. 241 /पु. वि.- 65 / 2018-19

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित बैंक/
सभी अनुसूचित शहरी बैंक/
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / एडीएफसी/
राज्य सहकारी बैंक/
राज्य सहकारी कृषि ग्रामीण विकास बैंक/
नाबार्ड पुनर्वित के लिए पात्र अन्य संस्थाएं अन्य.

प्रिय महोदय,

वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना -
"राष्ट्रीय पशुधन मिशन - ईडीईजी घटक" के कार्यान्वयन हेतु प्रशासनिक अनुमोदन.

हमें सहर्ष सूचित करते है कि पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 02 मई 2018 के अपने पत्र सं.99-6/2018/एनएलएम/ एडिएम. अप्रूवल के माध्यम से वर्ष 2018-19 के दौरान उपर्युक्त योजना को जारी रखने (07 अगस्त 2018 का मेमो सं. एफ.एन 99-6/2018/ एडिएम. अप्रूवल और 28 अगस्त 2018 के राष्ट्रीय पशुधन मिशन-एनएलएम, ईडीईजी के पत्र सं.2-47/2009-एएचटी/एफएंफ (वॉल्यूम III) के द्वारा दुर्गम क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों और एसएमबीसी घटक हेतु सब्सिडी सीमा के संबंध में परिचालनात्मक दिशानिर्देश) जारी रखने के लिए अनुमोदन दिया है.

वर्ष 2018-19 के लिए कुल रु.199.89 करोड़ का बजट आबंटित किया गया है और राज्य-वार श्रेणी-वार आबंटन अनुबंध I में दिया गया है. इस योजना को मूल्यांकन/ योजना के अनुमोदन के लंबित रहते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि से आगे विस्तार दिया गया है बशर्ते 12वीं योजना के लिए अनुमोदित इस योजना के प्रकृति, संभावना और व्याप्ति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. इसके विस्तृत परिचालनात्मक दिशानिर्देश www.dahd.nic.in पर उपलब्ध हैं.

2.राष्ट्रीय पशुधन मिशन के उद्यमिता विकास और रोजगार सृजन (ईडीईजी) के अधीन नाबार्ड कार्यान्वयक एजेंसी होगी. इसमें पोल्ट्री वेंचर कैपिटल फंड (पीवीसीएफ), छोटे रूमेन्यक और खरगोश समन्वित विकास (आईडीएसआरआर), सूअर विकास (पीडी), भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण (एसएमबीसी) शामिल हैं. उपर्युक्त उप-घटक अनुबंध - ए-I-(बी) में दिए गए हैं. विभिन्न क्षेत्रों के लिए सब्सिडी की दर और लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियां अनुबंध - ए-I-(सी) में दिए गए हैं.

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
पुनर्वित्त विभाग
प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बांद्रा (पू) मुंबई -400051
टेलि : +91 22 2652 4926 • फैक्स :+911 22 2653 0090
ई-मेल : dor@nabard.org • website :www.nabard.org

NABARD

National Bank for Agriculture and Rural Development
Department of Refinance
Head Office: BKC, Bandra (E), Mumbai – 400 051
Tel. +91 22 2652 4926 • Fax : +91 22 2653 0090
E-mail : dor@nabard.org • website : www.nabard.org

Ref No: NB. DoR /GSS/ 1510 /NLM-1/2018-19 14th September 2018

Circular No. 241 / DoR – 65 / 2018

The Chairman/ Managing Director
All Scheduled Commercial Banks/
All Scheduled Urban Banks,
Regional Rural Banks / ADFCs /
State Cooperative Banks /
State Cooperative Agriculture Rural Development Banks,
Other institutions eligible for NABARD refinance.

Dear Sir

Administrative Approval for implementation of Centrally Sponsored Scheme" National Livestock Mission-EDEG Component during 2018-19.

We are pleased to advise that the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India vide their letter no. 99-6/2018/NLM/Adm. Approval dated 2nd May 2018 has approved the continuation of the captioned Scheme for 2018-19,(vide Memo F.No.99-6/2018/NLM/Adm. Approval dt. 07 August 2018 and operational guidelines of NLM EDEG vide letter No.2-47/2009-AHT/FF (Vol. III) dt. 28 August 2018 for difficult areas, hill areas and subsidy ceiling for SMBC component).

The total budget allocation for 2018-19 is Rs.199.89 crores and the State wise category wise allocation is indicated in Annexure I. The scheme has been given interim extension beyond 12th plan period pending appraisal / approval of the scheme, subject to the condition that there shall be no change in nature, scope and coverage of the scheme as approved for the 12th plan. The detailed operational guidelines are available at www.dahd.nic.in.

2. NABARD will be the implementing agency under Entrepreneurship Development & Employment Generation (EDEG) component of National Livestock Mission. This includes i.e. Poultry Venture Capital Fund (PVCF), Integrated Development of Small Ruminants and Rabbit (IDSRR), Pig Development (PD), Salvaging of Male Buffalo Calves (SMBC). The sub-components of the above are furnished in Annexure –A-I (B). The rate of subsidy for various areas and various categories of the beneficiaries are furnished in Annexure –A-I (C).

3. The extract of the operational guidelines are as under;

I) Eligible Financial Institutions – Commercial Banks, Urban Banks, Regional Rural Banks, State Cooperative Banks, State Cooperative Agriculture and Rural Development Banks and such other Institutions eligible for refinance from NABARD.

II) Sanction of Project by Banks / Financial Institutions & Release of Subsidy – The entrepreneur will prepare a project report as per scheme norms and submit to the bank / financial institution for their sanction. The Bank / Financial Institution shall appraise the

3.परिचालनात्मक दिशानिर्देशों का सार नीचे दिया गया है:

I) पात्र वित्तीय संस्थाएं - वाणिज्य बैंक, शहरी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक और अन्य संस्थाएं जो नाबार्ड से पुनर्वित्त के लिए पात्र हैं.

II) बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा परियोजना की स्वीकृति और सब्सिडी जारी करना - उद्यमी योजना के मानदंडों के अनुसार, परियोजना रिपोर्ट तैयार करेंगे और इसकी स्वीकृति के लिए बैंक/ वित्तीय संस्था को प्रस्तुत करेंगे. पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी प्रशासनिक अनुमोदन के अनुसार बैंक / वित्तीय संस्थान परियोजना का मूल्यांकन करेंगे और पात्र पाए जाने पर ऋण कि स्वीकृति देंगे (कुल वित्तीय परिव्यय - मार्जिन राशि). बैंक/ वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद नियंत्रक कार्यालय स्वीकृति के 30 दिन के भीतर ईडीईजी पोर्टल में निर्धारित टेम्प्लेट के अनुसार जानकारी अपलोड करेंगे और पात्र सब्सिडी राशि ब्लॉक करेंगे. अपलोड करने और वेलिडेशन के बाद बैंक ऋण की पूरी राशि/ पहली किस्त, जैसा मामला हो, जारी करेगा. पूरे ऋण/ पहली किस्त की जानकारी पहले अपलोड के 30 दिन के भीतर अपलोड की जाएगी. इसके बाद, ऋण की राशि इकाई की प्रगति के आधार पर उचित किस्तों में वितरित की जाएगी.

बैंक/ वित्तीय संस्थाओं के नियंत्रक कार्यालय निर्धारित समय-सीमा के भीतर सब्सिडी के दावे अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा आवेदन सिस्टम से अपने आप हटा दिये जाएंगे, चूंकि बजट असीमित अवधि के लिए नहीं रखा जाता है.

अपूर्ण जानकारी या अन्य किसी कारणवश रद्द किए गए आवेदनों को आवश्यक सुधार करने के बाद नए सिरे से को फिर से अपलोड किया जाना होगा.

III) परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) - नाबार्ड प्रधान कार्यालय में गठित परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) संबंधित वित्तपोषक बैंक/ संस्थाओं द्वारा पोर्टल में अपलोड किए गए प्रस्तावों पर विचार करेगी और प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद एक महीने के भीतर पात्र आवेदकों के सब्सिडी के मामले अनुमोदित करेगी.

IV) राज्यों को श्रेणी-वार आबंटित बजट की उपलब्धता के अनुसार सब्सिडी जारी की जाएगी.

V) वित्तपोषक बैंक/ वित्तीय संस्था अपने बही खातों में सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में उधारकर्ता-वार सब्सिडी राशि रखेंगे और नाबार्ड से सब्सिडी प्राप्त होने के बाद सात दिन के भीतर लाभार्थी के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते में सब्सिडी की राशि का समायोजन करेंगे अन्यथा वित्तपोषक बैंक/ वित्तीय संस्था को लाभार्थी से लिए गए अतिरिक्त ब्याज की क्षतिपूर्ति करनी होगी. वित्तपोषक बैंक/ वित्तीय संस्था के नियंत्रक कार्यालय इस आशय का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे कि उन्होंने लाभार्थी संबंधी विस्तृत जानकारी सहित लाभार्थी के सब्सिडी आरक्षित निधि खाते (एसआरएफए) में सब्सिडी राशि जमा की है. सब्सिडी प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर नाबार्ड को यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत/ ऑनलाइन अपलोड करना होगा.

VI) चुकौती अवधि/ अनुग्रह अवधि :

ईडीईजी घटक	चुकौती अवधि	छूट अवधि
पोल्ट्री वेंचर पूंजी निधि (पीवीसीएफ)	5 से 9 वर्ष	6 माह से 1 वर्ष
छोटे रुमेन्थक और खरगोश समन्वित विकास (आईडीएसआरआर)	अधिकतम 9 वर्ष	2 वर्ष
सूअर विकास (पीडी)	5 से 6 वर्ष	1 वर्ष
भैंस के नर बछड़ों का संरक्षण (एसएमबीसी) (एसएमबीसी)	4 से 6 वर्ष	1 वर्ष

sanction loan (Total Financial Outlay (TFO) – Margin Money). After sanction of proposal by Banks / Financial Institutions, the controlling office will upload the details as per the templet prescribed in the EDEG Portal within 30 days of sanction and block eligible subsidy amount. On successful upload and post validation, the bank will release the entire credit / first instalment as the case may be. The details of entire credit / first instalment may be updated within 30 days of first upload. Thereafter, the loan amount shall be disbursed in suitable instalments, if required, depending on the progress of the unit.

The Banks/ Financial Institutions controlling office shall ensure the subsidy claims should be uploaded within stipulated time period failing which the system will delete the application automatically, as budget cannot be earmarked for unlimited period.

The applications rejected due to incomplete details or any other reason, the applications has to be uploaded afresh after making necessary corrections.

III) Project Sanctioning Committee (PSC) – The Project Sanctioning Committee (PSC) set up at NABARD Head Office shall consider proposals uploaded by Concerned Financing Bank / Institutions in portal and approve the subsidy cases of eligible applicants within one month of receipt of the proposal.

IV) The subsidy will be released subject to availability of the category-wise funds allocated to the states.

V) The financing Bank / institution would keep subsidy amount borrower-wise in "Subsidy Reserve Fund Account in their books of accounts and adjust the subsidy amount in the subsidy reserve fund account of the beneficiary within seven days of the receipt of subsidy from NABARD failing which the financing bank / financial institution shall be liable to compensate the beneficiary to the extent of the additional interest charged. The controlling office of the financing bank / institution shall submit utilization certificate to the effect that the subsidy amount has been credited to the Subsidy Reserve Fund Account (SRFA) of the beneficiary along with details of the beneficiary. The certificate should be submitted / uploaded to NABARD online within fifteen days of receipt of subsidy.

VI) Repayment period / grace period -

EDEG Component	Repayment Period	Grace Period
Poultry Venture Capital Fund (PVCF)	5 to 9 years	6 months to 1 year
Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits (IDSRR)	Maximum 9 Years	2 Years
Pig Development (PD)	5 to 6 years	1 Year
Salvaging of Male Buffalo Calves (SMBC)	4 to 6 years	1 Year

VII) Time limit for completion of the project - Time limit for completion of project would be as envisaged under the project subject to maximum of 12 months from the date of disbursement of first instalment of loan. This maximum period may be extended by 3 months by the financing bank in cases where justification given by the beneficiary is found adequate.

VIII) Lock in Period for subsidy – 3 years i.e. subsidy can be adjusted to borrowers account after period of three years and shall be returned if the account becomes a Non Performing Asset (NPA).

IX) Margin Money - RBI guidelines to be followed as applicable from time to time.

VII) परियोजना पूर्ण करने की समय-सीमा: परियोजना में किए गए प्रावधान के अनुसार ऋण की पहली किस्त के वितरण तिथि के बाद अधिकतम 12 महीने के भीतर परियोजना पूरी करनी होगी. लाभार्थी द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण पर्याप्त पाए जाने पर वित्तपोषक बैंक इस अधिकतम अवधि को 3 महीने तक बढ़ा सकता है.

VIII) सब्सिडी के लिए लॉक-इन पीरियेड - 3 वर्ष: 3 वर्ष की अवधि के बाद सब्सिडी की राशि उधारकर्ता के खाते में समायोजित की जा सकती है . अनर्जक आस्ति खाते (एनपीए) के बनने पर इसे लौटाया जाएगा.

IX) मार्जिन राशि: भारतीय रिज़र्व बैंक से समय-समय पर जारी दिशानिर्देश लागू होंगे.

X) सहायता प्रदान करने में वरीयता - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन, छोटे, सीमांत और देश के सूखा और बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों सहित गरीबी रेखा के नीचे आने वाले किसानों की श्रेणी में आने वाले लाभार्थीयों को वरीयता दी जा सकती है.

5. अनुप्रवर्तन और रिपोर्टिंग - स्थापित की गई इकाइयों का नमूना आधार पर अनुप्रवर्तन नाबार्ड करेगा और प्रमुख टिप्पणियाँ परियोजना स्वीकृति समिति (पीएससी) के समक्ष प्रस्तुत करेगा.

6. अपनी संबंधित शाखाओं को इस परिपत्र की विषय-वस्तु के अवगत कराएं.

कृपया पावती दें.

भवदीय

(जी.आर.चिंताला)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्नक : यथोपरि

X) Priority in Providing Assistance - Priority may be given to the beneficiaries from the categories of Scheduled Caste, Scheduled Tribe, landless, small, marginal and BPL category farmers along with farmers belonging to drought and flood affected areas of the country.

5. Monitoring and Reporting - The units set up will be monitored by NABARD on sample basis and major observation would be placed before the Project Sanctioning Committee (PSC).

6. This may be brought to the notice of your concerned branches.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully

(G R Chintala)
Chief General Manager

Encl: As Above

परांकन: ऊपरयुक्त दिनांक के पत्र सं. राबैं(डीओआर)/जीएसएस/ 1511 /डीईडीएस-1/ 2018-19
की प्रतिलिपि जानकारी तथा आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रस्तुत

Endt. No. NB. DoR / 1511 / GSS-AH/ NLM-1/ 2018-19 of date.

Copy forwarded for information / necessary action to:

1. सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली 110001

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Agriculture and Cooperation, Krishi Bhavan, New Delhi - 110001

2. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

2. The Secretary, Government of India, Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Rural Development, Krishi Bhavan, New Delhi - 110001

3. निदेशक (सीएसआर), कृषि और सहकारिता विभाग, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, प्रधान कार्यालय, नई सीजीओ बिल्डिंग, रा. म. 4, फ़रीदाबाद - 121001

3. The Director (CSR), Government of India, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture & Cooperation, Directorate of Marketing and Inspection, Head Office, New CGO Building, NH IV, Faridabad - 121001.

4. सचिव, बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001

4. The Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi - 110001

5. सचिव, नीति आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

5. The Secretary, NITI Aayog, Yojana Bhavan, Parliament Street, New Delhi - 110001

6. निदेशक (सहकारिता), नीति आयोग, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001

6. The Director(Cooperation),NITI Aayog, Yojana Bhavan, Parliament Street, New Delhi-110001

7. उपायुक्त(ऐसी), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001.

7. The Deputy Commissioner (AC), Ministry of Agriculture and Rural Development, Department of Agriculture and Co-operation, Government of India, New Delhi – 110001.

8. निदेशक (आयएडीपी) (सहकारिता), विस्तार निदेशालय, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001.

8. The Director (IADP) (Co-operation), Directorate of Extension, Ministry of Agriculture and Rural Development, Government of India, New Delhi - 110001

9. निदेशक (ऋण), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली - 110001.

9. The Director (Credit), Department of Agriculture and Co-operation, Ministry of Agriculture and Rural Development, Government of India, New Delhi – 110001.

10. अध्यक्ष, भारतीय बैंकर्स संस्था, ब्लॉक 2 और 3, स्टेडियम हाऊस, छटी मंज़िल, 81-83, वीर नरीमन रोड, मुंबई 40020.

10. The Chairman, Indian Banks Association, Blocks 2 & 3, Stadium House, 6th Floor, 81-11, Veer Nariman Road, Mumbai 400020.

11. मुख्यमहाप्रबंधक, ग्रामीण योजना और ऋण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, प्रधान कार्यालय, मुंबई - 400023

11. The Chief General Manager, Rural Planning and Credit Department, Reserve Bank of India, Central Office, Mumbai - 400023.

12. सहकारी समिति निबंधक, सभी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश.

12. The Registrar of Co-operative Societies, All States/Union Territories.

13. प्रबंध निदेशक, रासकृग्राविबैं महासंघ, 701 बीएसईएल टेक पार्क, VII वि मंज़िल, 'ऐ' विंग, रेल्वे स्थानक के सामनें, वाशी, नवी मुंबई - 400 705

13. The Managing Director, SCARDB Federation, 701 BSEL Tech Park, VII Floor, 'A' Wing, Opp. Railway Station, Vashi, Navi Mumbai - 400 705.

14. अतिरिक्त आयुक्त (वि.), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001

14. Additional Commissioner (Extn.), Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhavan, New Delh – 110001.

15. संयुक्त सचिव, कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110012

15. Joint Secretary (Extn.), Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi - 110012.

16. सामान्य निदेशक, म्यानेज, राजेंद्र नगर, हैदराबाद, आंध्रा प्रदेश - 500030

16. Director General, MANAGE, Rajendra Nagar, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500030.

17. निदेशक (वित्त), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001

17. Director (Finance), Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi – 110001.

18. उप सामान्य निदेशक (वि.), आईसीएआर, कृषि अनुसंधान भवन, नई दिल्ली - 110012.

18. Deputy Director General (Extn), ICAR, Krishi Anusandhan Bhavan, New Delhi – 110012.

19. अतिरिक्त आयुक्त (वि.), कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली - 110001.

19. Additional Secretary (Extn.), Department of Agriculture and Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi – 110001.

20. उप कुलाधिपति, सभी राज्य कृषि विश्वविद्यालय.

20. Vice Chancellors of All State Agricultural Universities.

21. सचिव (ऐ और सी), कृषि और सहकारिता विभाग, सभी राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश.

21. Secretary (A & C), Department of Agriculture & Cooperation, All States/UTs.

22. अध्यक्ष के आर्थिक सलाहकार, नाबार्ड, प्रका, मुंबई.

22. EA to Chairman, NABARD, HO, Mumbai.

23. उपप्रबंधनिदेशक के आर्थिक सलाहकार, नाबार्ड, प्रका, मुंबई

23. EA to DMDs, NABARD, HO, Mumbai.

24. मुमप्र / प्रअ, नाबार्ड, सभी क्षेत्रीय कार्यालय और प्रशिक्षण प्रतिष्ठान.

24. CGM / OIC, NABARD, ALL ROs and Training Establishments.

(के. सुरेश कुमार / K. Suresh Kumar)
उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager

ANNEXURE - I

Budgetary allocation for Component-EDEG of National Livestock Mission for FY 2018-19

*Allocation for other than NER States for FY 2018-19

(Rs. In lakh)

S. No.	Name of the State / UTs	General / Others	Scheduled Tribe	Scheduled Caste	Total
1	And. & Nic. Island	17	2	0	19
2	Andhra Pradesh	2500	300	647	3447
3	Bihar	597	45	86	728
4	Chhattisgarh	527	265	135	927
5	Dadra & Nagar Haveli	9	6	2	17
6	Daman & Diu	10	1	2	13
7	Goa	7	1	2	10
8	Gujarat	188	50	25	263
9	Haryana	148	0	55	203
10	Himachal Pradesh	195	26	70	291
11	Jammu & Kashmir	425	115	70	610
12	Jharkhand	38	14	20	72
13	Karnataka	1500	245	470	2215
14	Kerala	917	78	200	1195
15	Lakshadweep	1	9	0	10
16	Madhya Pradesh	92	27	35	154
17	Maharashtra	2000	250	358	2608
18	Odisha	50	20	13	83
19	Punjab	294	0	130	424
20	Rajasthan	450	60	59	569
21	Tamilnadu	1500	60	540	2100
22	Telangana	1260	87	177	1524
23	Uttar Pradesh	268	23	100	391
24	Uttarakhand	487	77	162	726
25	West Bengal	239	35	78	352
26	NCT of Delhi	2	0	1	3
27	Puducherry	25	0	10	35
	Total (A)	13746	1796	3447	18989

*Allocation for NER States for FY 2018-19

(Rs. In lakh)

S. No.	Name of the State	General / Others	Scheduled Tribe	Scheduled Caste	Total
1	Arunachal Pradesh	81	9	0	90
2	Assam	384	51	85	520
3	Manipur	17	2	10	29
4	Meghalaya	24	3	4	31
5	Mizoram	92	12	5	109
6	Nagaland	145	19	0	164
7	Sikkim	15	2	10	27
8	Tripura	17	2	11	30
	Total (B)	775	100	125	1000
	Grand TOTAL (A)+(B)	14521	1896	3572	19989

* The above are only indicative allocation and are subject to modification and changes according to Regular Budgetary Allocations for 2018-19 and pending claims lying with States/Uts.

Annexure-A-I (B)

Sub-mission: Livestock Development
Indicative subsidy ceilings under the component of Entrepreneurship Development and Employment Generation" (EDEG)

Sub-component - Poultry Venture Capital Fund (PVCF)-EDEG		
S. No.	**Component**	**Ceiling of Subsidy**
I	Breeding Farms for Birds of alternate species like turkey, ducks, Japanese quails, guinea fowl and geese.	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 7.50 lakh Varies depending on the species and unit size.
II	Central Grower Units (CGU) – upto 16000 layer chicks per batch.	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 10 lakh for a unit of 16000 layer chicks per batch (three batches a year) Minimum unit size – 16000 layer chicks per batch.
III	Hybrid Layer (chicken) Units – upto 20000 layers.	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 2 lakh for 2000 layer unit – Varies with size. Minimum unit size – 2000 layer.
IV	Hybrid Broiler (chicken) Units – upto 20000 birds. Can be weekly, fortnightly, monthly, all-in all-out batches. Bird strength at any point of time should not exceed 20000 birds	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 0.56 lakh for a batch of 1000 broilers - Varies with size. Minimum unit size – 1000 Broilers.
V	Rearing of Poultry like low-input technology variety of chicken and other alternative species like turkey, ducks, Japanese quails, guinea fowl and geese.	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 5 lakh Varies with the species and unit size.
VI	Feed Mixing units (FMU) - 1.0 ton per hour. Disease Investigation Lab (DIL)	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 4 lakh.
VII	Transport Vehicles – open cage	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 2 lakh
VIII	Transport Vehicles – Refrigerated	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 3.75 lakh
IX	Retail outlets – Dressing units	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 2.50 lakh
X	Retail outlets – marketing units	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 3.75 lakh
XI	Mobile marketing units	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 2.5 lakh
XII	Cold storage for poultry products	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 5 lakh
XIII	Egg / Broiler Carts	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 3750/-
Sub-component - Integrated Development of Small Ruminants and Rabbits (IDSRR)-EDEG		
I	Commercial Units of 10 ewe / does+ 1 ram / buck	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 12,500/- Minimum unit size 10 ewe/does + 1 ram/buck. (Maximum 4 units.)
II	Breeding farms with 100 ewe / does + 5 ram / bucks	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs.2,50,000/-. Minimum and Maximum unit size 100 ewe/does + 5 ram / bucks.

III	Commercial rabbit -Angora units with 15 females + 5 males	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 75,000/-. Minimum and Maximum unit size 15 females + 5 males.
IV	Rabbit - Angora breeding Farms with 15 females + 5 males	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 75,000/- Minimum and Maximum unit size 15 females + 5 males.
Sub-component - Pig Development-EDEG		
I	Commercial rearing units (3 sows + 1 Boar)	At 25% level subsidy- subsidy ceiling Rs. 25,000/- Minimum unit size 3 sows + 1 Boar. (Maximum 4 units.)
II	Pig Breeding Farms (20 sows + 4 Boars)	At 25% level subsidy - subsidy ceiling Rs. 2,00,000/-. Minimum and Maximum unit size 20 sows + 4 Boars.
III	Retail Pork Outlets with facility for chilling	At 25% level subsidy - subsidy ceiling Rs. 3,00,000/-.
Sub-component - Salvaging of Male Buffalo Calves-EDEG		
I	Mini Units: Rearing of male Buffalo calves upto 25 calves.	At 25% level subsidy - subsidy ceiling Rs. 6,250/- per calf. It would be implemented by the NABARD. The beneficiary will have to avail bank loan to a tune of minimum 50% of project cost minus subsidy and prescribed beneficiaries share.
II	Commercial Units: Rearing of male Buffalo calves, more than 25 calves upto 200 calves at one location.	At 25% level subsidy - subsidy ceiling Rs. 1,50,000/- per 25 calves (at the rate of Rs.6,000/- per calf). It would be implemented by the NABARD. The beneficiary will have to avail bank loan to a tune of minimum 50% of project cost minus subsidy and prescribed beneficiary share.
III	Industrial Rearing Units: more than 200 calves upto 2000 Buffalo calves at one location.	At 25% level subsidy - subsidy ceiling Rs. 6,25,000/- per 200 calves (at the rate of Rs.3,125/- per calf). It would be implemented by the APEDA and subsidy would be channelized through NABARD. The beneficiary will have to avail bank loan to a tune of minimum 50% of project cost minus subsidy and prescribed beneficiary share.

Note:- *(a)* The ceiling on subsidy in general is at the rate of 25%. Pro-rata variable subsidy depending on category of beneficiary and location of the project will be applicable. The unit cost assumed for calculation of ceiling of subsidy is indicative only and Joint Monitoring Committee, NLM can revise or modify as per the prevailing market price in the area, based on inputs from SLMC/NABARD.
(b) Rearing of male buffalo calves for a minimum period of 24 months.
(c) All units under "Entrepreneurship Development and Employment Generation", include provisions for feed and fodder, silage making, biosecurity and healthcare, insurance and other project activities etc.
(d) An entrepreneur may avail more than one unit (maximum 4 units) of Commercial Unit of 10 ewe / does+ 1 ram / buck and; Commercial rearing units (3 sows + 1 Boar).
(e) No multiple unit will be allowed for other activities under the Component- EDEG.
(f) The back ended subsidy will be restricted to 25% - 40% for Salvaging of Male Buffalo Calves, depending upon various areas and categories i.e. maximum 40% for BPL/SC/ST categories of North East Region / Hill Areas / LWE affected districts and BPL/SC/ST/ APL categories of Difficult Areas.

Annexure-A-I(C)

Proportion of Subsidy for various areas and various categories of beneficiaries.

NORMAL AREAS:

Category	Back ended subsidy	Credit	Beneficiary Share / Margin Money
BPL / SC / ST	33.33%	56.67%	10%
APL	25%	65%	10%

NORTH EAST REGION / HILL AREAS / LWE AFFECTED DISTRICTS

Category	Back ended subsidy	Credit	Beneficiary Share / Margin Money
BPL / SC / ST	50%	40%	10%
APL	35%	55%	10%

DIFFICULT AREAS

Category	Back ended Subsidy	Credit	Beneficiary Share / Margin Money
BPL / SC / ST	60%	30%	10%
APL	45%	45%	10%

Abbreviations: BPL: Below Poverty Line, SC / ST: Schedule Caste / Schedule Tribe, APL: Above Poverty Line

TYPES OF AREAS:

NORMAL AREAS: All areas which do not fall under the subsequent categories.

NORTH EAST REGION: Seven NE States and Sikkim

HILL AREAS: Designated Hill Areas indicated below:

State	Districts	State	Districts
Assam	North Cachar Karbi Anglong	West Bengal	Darjeeling
Uttarakhand	Dehradun Pauri Garhwal Tehri Garwhal Chamoli Uttarkashi Nainital Almora Pithoragarh	Himachal Pradesh	Chamba Kinnaur Kullu Lahauland Spiti Shimla Kangra
Jammu & Kashmir	Kathua Udhampur Doda Baramulla	Tamil Nadu	Nilgiris
Mizoram	Chimptuipui Lungelei Town in Lunglei District		

Notified Left Wing Extremist Affected Districts (90 Nos.)

Andhra Pradesh	Jharkhand	Odisha (cont.)
1.East Godavari	37.Bokaro	71.Nayagarh
2.Guntur	38.Chatra	72.Nuapada
3.Srikakulam	39.Dhanbad	73.Rayagada
4.Visakhapatnam	40.Dumka	74.Sambhalpur
5.Vizianagaram	41.East Singhbhum	75.Sundargarh
6.West Godavari	42.Garhwa	
	43.Giridih	**Telangana**
Bihar	44.Gumla	76.Adilabad
7.Arwal	45.Hazaribagh	77.Bhadradri-Kothagudem
8.Aurangabad	46.Khunti	78.Jayashanker-Bhupalpally
9.Banka	47.Koderma	79.Khammam
10.East Champaran	48.Latehar	80.Komaram-Bheem
11.Gaya	49.Lohardaga	81.Mancherial
12.Jamui	50.Palamu	82.Peddapalle
13.Jehanabad	51.Ramgarh	83.Warangal Rural
14.Kaimur	52.Ranchi	
15.Lakhisarai	53.Simdega	**Uttar Pradesh**
16.Munger	54.Saraikela-Kharaswan	84.Chandauli
17.Muzaffarpur	55.West Singhbhum	85.Mirzapur
18.Nalanda		86.Sonebhadra
19.Nawada	**Madhya Pradesh**	
20.Rohtas	56.Balaghat	**West Bengal**
21.Vaishali	57.Mandla	87.Jhargram
22.West Champaran		
	Maharashtra	**Kerala**
Chhattisgarh	58.Chandrapur	88.Malappuram
23.Balod	59.Gadchiroli	89.Palakkad
24.Balrampur	60.Gondia	90.Wayanad
25.Bastar		
26.Bijapur	**Odisha**	
27.Dantewada	61.Angul	
28.Dhamtari	62.Bargarh	
29.Gariyaband	63.Bolangir	
30.Kanker	64.Boudh	
31.Kondagaon	65.Deogarh	
32.Mahasamund	66.Kalahandi	
33.Narayanpur	67.Kandhamal	
34.Rajnandgaon	68.Koraput	
35.Sukma	69.Malkangiri	
36.Kabirdham	70.Nabrangpur	

DIFFICULT AREAS: Notified Difficult Areas like Leh, Ladakh, Kargil areas, areas above 11,000 ft. height from mean sea level as well as difficult islands.

Note: List of Hill areas, Notified Left Wing Extremist Affected Districts and Difficult areas will be in line with time to time updated/notified list of related Ministries/Departments of Government of India.

EDEG Claims Format

Annexure 1

Sr. No	Title (Mr/Mrs) (M)	First Name (M)	Middle Name (M)	Last Name (M)	End Beneficiary Date of Birth (dd-mm-yy)(M)	Beneficiary Aadhar Card No. (M)	Gender (M/F) (M)	Category (Gen/Sc/St) (M)	Income Criteria (Below poverty line/above poverty line)(M)	Beneficiary Address (Preferable as per Aadhar Card)(M)	Beneficiary Mobile Number (M)	Beneficiary Mail Address (O)	Branch IFSC Code (IFSC code of Bank, Where PLDB account is maintained)(M)	Branch E-mail (M)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Beneficiary Loan A/C Number (M)	Purpose of Loan (M)	Project Block (M)	Project Village (M)	Data of Receipt of the Application by Bank (dd-mm-yy) (M)	Date of Sanction (dd-mm-yy)(M)	Repayment Period (In Months) (M)	Interest Rate (in%) (M)	Unit Number (M)	Updated Total Project Cost as per Beneficiary (As per application) (M)	project Cost (TFO) as per PLDB (M)	Bank Loan (M)	Margin Money (min.10% of Project cost) (M)	Eligible Subsidy
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

EDEG Claims Format

(Annexure -2)

s.no.	Title(M) Mr./Mrs.	First Name(M	Middle Name(O)	Last Name(M)	End Benefi Ciary Date of Birth(M)	Beneficiary Aadhar Card No.(M)	Gender male/ female (M)	Category (M) Gen./Sc/ ST	Income Criteria (M) Above or Below poverty line	Beneficiary s Address (Perferable as per Aadhar Card (M)	Beneficiary s Mobile no. (M)	Beneficiary e-mail address (O)	Branch IFSC Code (IFSC code of Bank,where PLDB account is maintained) (M)	Branch E-mail (M)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Beneficiary Loan a/c no. (M)	Purpose of Loan (M)	Project Block (M)	Project Viillage (M)	Date of Receipt of the Application by Bank (M)	Date of Sanction (M)	**Date of release of 1st installment of loan (M)**	**Amount of 1st installment of loan released (M)**	Repayment Period (in Months) (M)	Interest Rte (in %) (M)	Unit Number (M)	Updated Total project cost as per Beneficiary (As per application) (M)	Project Cost (TFO) as per PLDB (M)	Bank Loan (M)	margin Money (Min. 10% of project cost) (M)	Eligible Subsidy
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31